PUBLIC INTEREST DISCLOSURE & PROTECTION OF INFORMERS (PIDPI) RESOLUTION, 2004

ISO 9001:2015

What is PIDPI

- PIDPI means Public Interest Disclosure and Protection of Informers.
- It is a resolution of Government of India under which Central Vigilance Commission (CVC) is authorized as the 'Designated Agency' to receive written complaints for disclosure on any allegation of corruption or misuse of office and also to recommend appropriate action.

Jurisdiction

- PIDPI is restricted to any employee of the Central Government or of any corporation established by or under any Central Act.
- Personnel employed by the State Governments and activities of the State Governments or its Corporations do not come under CVC.

Steps to be followed by Complainant

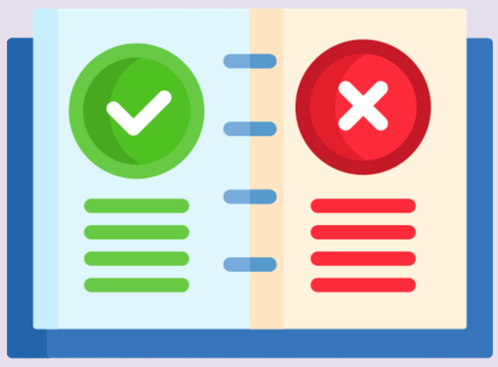

- Keep the complaint only in a closed / secured envelope.
- Address the envelope to Secretary, Central Vigilance Commission and superscript it "Complaint under The Public Interest Disclosure"
- Complainant should not give any details or clue of his/her identity.
- Complainant is advised not to enter into any further correspondence with the Commission in their own interest.
- Commission will not entertain anonymous/ pseudonymous complaints.

Note: The Commission can take action against complainants making motivated/vexatious complaints.

Issued in Public Interest by the Central Vigilance Commission, https//www.cvc.gov.in

VIGILANCE AWARENESS WEEK 2023

सार्वजनिक हित प्रकटीकरण एवं मुखबिरों की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) संकल्प, 2004

ISO 9001:2015

पीआईडीपीआई क्या है???

- पीआईडीपीआई का मतलब सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा है।
- यह भारत सरकार का एक संकल्प है जिसके तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को 'नामित एजेंसी' के रूप में अधिकृत किया गया है जो भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप के खुलासे के लिए लिखित शिकायतें प्राप्त करेगा और उचित कार्रवाई की सिफारिश भी करेगा।

न्याय सीमा

- पीआईडीपीआई केंद्र सरकार या किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित निगम के कर्मचारियों तक ही सीमित है।
- राज्य सरकारों द्वारा नियोजित कार्मिक और राज्य सरकारों या उसके निगमों की गतिविधियाँ सीवीसी के अंतर्गत नहीं आती हैं।

शिकायतकर्ता द्वारा अपनाए जाने वाले कदम

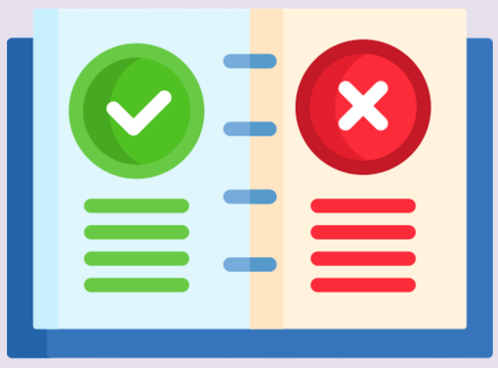

- शिकायत को बंद/सुरक्षित लिफाफे में ही रखें।
- लिफाफे को सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग को संबोधित करें और उस पर "सार्वजनिक हित प्रकटीकरण के तहत शिकायत" लिखें।
- शिकायतकर्ता को अपनी पहचान का कोई विवरण या सुराग नहीं देना चाहिए।
- शिकायतकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में आयोग के साथ आगे कोई पत्राचार न करें।
- आयोग गुमनाम / छद्मनाम शिकायतों पर विचार नहीं करेगा।

नोट: आयोग प्रेरित/परेशान करने वाली शिकायतें करने वाले शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जनहित में जारी, https//www.cvc.gov.in

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023

सार्वजनिक हिताचे प्रकटीकरण आणि गुप्त बातमीदाराचे संरक्षण (पीआयडीपीआय) ठराव, 2004

ISO 9001:2015

पीआयडीपीआय काय आहे??

- पीआयडीपीआय म्हणजेच सार्वजनिक हिताचे प्रकटीकरण आणि गुप्त बातमीदाराचे संरक्षण.
- हा भारत सरकारचा एक ठराव आहे ज्याद्वारे केंद्रीय दक्षता आयोगाला (CVC) भ्रष्टाचार किंवा पदाचा गैरवापर केल्याच्या कोणत्याही आरोपाच्या प्रकटीकरणासाठी लेखी तक्रारी प्राप्त करण्यासाठी 'नियुक्त एजन्सी' म्हणून अधिकृत करण्यात आले आहे आणि योग्य कारवाईची शिफारस देखील करेल.

न्याय मर्यादा

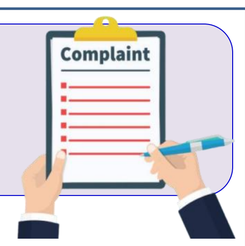

- पीआयडीपीआय हे केंद्र सरकारच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यासाठी किंवा कोणत्याही केंद्रीय कायद्याद्वारे किंवा त्याअंतर्गत स्थापन केलेल्या कोणत्याही कॉर्पोरेशनपुरते मर्यादित आहे.
- राज्य सरकारांद्वारे नियुक्त केलेले कर्मचारी आणि राज्य सरकारे किंवा त्यांच्या कॉर्पोरेशनचे CVC अंतर्गत येत नाहीत.

तक्रारदाराने उचलायची पावले

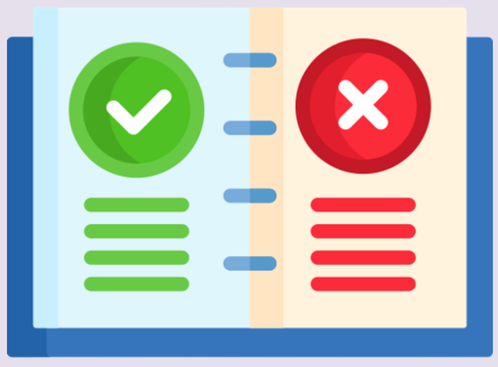

- तक्रार फक्त बंद/सुरक्षित लिफाफ्यात ठेवा.
- लिफाफा सेक्रेटरी, सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशन यांना संबोधित करा आणि "सार्वजनिक हिताच्या प्रकटीकरणाखाली तक्रार" वर लिहा.
- तक्रारदाराने त्याच्या ओळखीचे कोणतेही तपशील किंवा संकेत देऊ नयेत.
- तक्रारदाराला त्यांच्या स्वत:च्या हितासाठी आयोगाशी कोणताही पत्रव्यवहार न करण्याचा सल्ला दिला जातो.
- आयोग निनावी / टोपणनाव तक्रारींची दखल घेणार नाही.

टीप: आयोग प्रवृत्त/छळवणूक करणाऱ्या तक्रारी करणाऱ्यांवर कारवाई करू शकतो.

केंद्रीय दक्षता आयोगाने सार्वजनिक हितासाठी जारी केले, https//www.cvc.gov.in

दक्षता जनजागृती सप्ताह 2023